अध्याय 6

मूल्य प्रवृत्तियां

श्रम ब्यूरो श्रम और रोजगार मंत्रालय का एक संबद्ध कार्यालय है, इसकी स्थापना के बाद से इसे अन्य बातों के अलावा औद्योगिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के संकलन, रखरखाव और प्रसार की जिम्मेदारी सौंपी गई है। सीपीआई–आईडब्ल्यू को अंतर्राष्ट्रीय सर्वोत्तम प्रथाओं और आईएलओ के दिशानिर्देशों के अनुसार संकलित किया गया है और सीपीआई– आईडब्ल्यू का प्रसार विशेष डेटा प्रसार मानक (एसडीडीएस) के अनुपालन है। यह उक्त महीने के अंतिम कार्य दिवस पर जारी किया जाता है। सीपीआई–(आईडब्ल्यू) श्रम ब्यूरो, श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा संकलित और जारी किए जाते हैं और जनसंख्या क्षेत्रों के लिए विशिष्ट हैं।

1.1 औद्योगिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक सीपीआई–(आईडब्ल्यू), एक प्रमुख आर्थिक संकेतक है, यह एक आधार वर्ष के संदर्भ में किसी दिए गए क्षेत्र में एक औसत कामकाजी वर्ग के परिवार द्वारा उपभोग की जाने वाली वस्तुओं और सेवाओं के एक निश्चित सेट के संबंध में समय–समय पर खुदरा कीमतों में सापेक्ष परिवर्तनों को मापता है। सीपीआई–(आईडब्ल्यू) का उपयोग मुख्य रूप से महंगाई भत्ते (डीए) के विनियमन और निर्धारण के लिए किया जाता है, जो बड़ी संख्या में केंद्रीय/राज्य सरकार के कर्मचारियों को भुगतान किया जाता है और साथ ही औद्योगिक क्षेत्रों में कामगारों को निर्धारित रोजगार में न्यूनतम मजदूरी के निर्धारण और संशोधन के लिए भी दिया जाता है, अतः सरकारी खजाने पर इसका महत्वपूर्ण वित्तीय प्रभाव पड़ता है। इसके अलावा सीपीआई आंकड़ों का व्यापक इस्तेमाल मंहगाई के बृहत्त आर्थिक संकेतकों के रूप में भी किया जाता है और सरकार एवं केन्द्रीय बैंकों द्वारा मंहगाई और मूल्य स्थिरता नियंत्रण के लिए भी इनका इस्तेमाल किया जाता है।

1.2 सितंबर, 2020 के महीने से श्रम ब्यूरो ने सीपीआई–आईडब्ल्यू (2001=100) की मौजूदा श्रृंखला के आधार को नए आधार 2016=100 में अपडेट कर दिया है। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक संख्याओं के निर्माण के मुख्य घटक भार और मूल्य हैं। आधार अवधि के दौरान प्रत्येक वस्तु पर वास्तविक व्यय का हिस्सा, भार होता है और इंडेक्स बास्केट में रखी गई वस्तुओं के संबंध में आधार मूल्य 2016 के दौरान वस्तुओं की कीमतों का वार्षिक औसत है।

1.3 सीपीआई के संकलन के लिए अपनाए गए मूल्य की परिभाषा वह मूल्य है जो किसी उपभोक्ता/औद्योगिक श्रमिक को निर्दिष्ट इकाई के लिए निर्दिष्ट वस्तु/किस्म के लिए, चयनित बाजार की चयनित दुकान में भुगतान करना होता है। इसमें बिक्री कर, आदि जैसे सभी कर शामिल हैं, और रियायत और छूट शामिल नहीं हैं, जो सभी ग्राहकों के लिए सार्वभौमिक रूप से लागू हैं। यह खुले बाजार में प्रचलित वास्तविक मूल्य है जिस पर खरीदार और विक्रेता के बीच लेनदेन होता है। हालांकि, काला बाजार या अनधिकृत मूल्य सूचकांक संख्याओं के संकलन में नहीं लिए गए हैं। राशन की वस्तुओं के मामले में उचित मूल्य लिया जाता है।

1.4 उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई) एक निर्दिष्ट अवधि में निर्दिष्ट वस्तुओं एवं सेवाओं के खुदरा मूल्यों में परिवर्तन को इंगित करता है, जबकि थोक मूल्य सूचकांक (डब्ल्यूपीआई) थोक बिक्री स्तर पर वस्तुओं के सामान्य मूल्य स्तर में परिवर्तन को दर्शाता है। डब्ल्यूपीआई प्राथमिक पैमाना है

जिसका इस्तेमाल महंगाई का पता लगाने के लिए किया जाता है क्योंकि यह किसी निर्दिष्ट क्षेत्र में, निर्दिष्ट समयावधि के दौरान निर्दिष्ट श्रेणी की वस्तुओं या सेवाओं के मूल्यों में परिवर्तन के लिए जिम्मेदार होता है। मूल्य सूचकांकों के अनेक संभावित उपयोग होते हैं। सूचकांक का इस्तेमाल मूल्यों में परिवर्तन मापने या रहन–सहन की लागत का आकलन करने में किया जा सकता है।

कुछ जाने माने मूल्य सूचकांक इस प्रकार हैं :–

I. थोक मूल्य सूचकांक – अखिल भारतीय (डब्ल्यूपीआई)
II. औद्योगिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई–आईडब्ल्यू)
III. कृषि श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई–एएल)
IV. ग्रामीण श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई–आरएल)

1.5 आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों में भारी परिवर्तन का असर उत्पादन की मात्रा और उपभोग के पैटर्न, दोनों पर पड़ता है। मूल्यों में बदलाव का प्रभाव आम लोगों के जीवन स्तर और विशेष कर निर्धनों की जीवन स्थितियों पर पड़ता है। इसलिए, मूल्य व्यवहार पर निरंतर निगरानी रखना अत्यंत अनिवार्य है। सांख्यिकीय दृष्टि से मूल्य सूचकांक एक निर्दिष्ट अवधि में मूल्यों में परिवर्तन का आकलन करता है। मूल्य सूचकांकों की गणना थोक बिक्री स्तर और खुदरा बिक्री स्तर पर की जाती है।

1.6 थोक बिक्री मूल्य सूचकांक (डब्ल्यूपीआई) एकमात्र सामान्य सूचकांक है, जो व्यापक तौर पर मूल्यों में उतार चढ़ाव का आकलन करता है और सभी प्रकार के व्यापार और लेनदेन में वस्तुओं के मूल्यों में परिवर्तनों का द्योतक है। इसे आमतौर पर अर्थव्यवस्था में महंगाई की दर के संकेतक के रूप में समझा जाता है। डब्ल्यूपीआई की मौजूदा श्रृंखलाएं आधार वर्ष (2011–12=100) की तुलना में एक निश्चित अवधि के भीतर थोक मूल्यों में परिवर्तन दर्शाती हैं। 2016–17 से 2022–23 की अवधि में थोक मूल्य सूचकांक की वर्षवार तुलना तालिका 6.1 में दी गयी है।

2. थोक मूल्य सूचकांक के संकलन की पद्धति

2.1 थोक मूल्य, विशेषकर प्राथमिक स्तर पर किसी वस्तु के बल्क व्यापार के निर्दिष्ट मूल्य को प्रस्तुत करता है। भारत में 2011–12 को आधार वर्ष मानते हुए थोक मूल्य सूचकांक की संशोधित (वर्तमान) श्रृंखला ने अभी तक प्रचलित डब्ल्यूपीआई श्रृंखला का स्थान ले लिया है, जिसका आधार वर्ष 2004–05 था। मौजूदा श्रृंखला भारित गणितीय औसत के सिद्धांत पर आकलित की गयी है।

2.2 मूल्य सापेक्षकों की गणना प्रतिशत अनुपातों के रूप में की जाती है, जिसे वर्तमान मूल्यों के संदर्भ में आधार अवधि में प्रचलित मूल्यों की तुलना में आकलित किया जाता है। दूसरे शब्दों में, प्रत्येक किस्म/कोटेशन के लिए मूल्य सापेक्ष की गणना वर्तमान मूल्य को समनुरूप आधार अवधि (2011–12) के मूल्य से विभाजित करते हुए और इस तरह प्राप्त होने वाली संख्या को 100 से गुणा करके की जाती है। वस्तु विशेष के लिए चुनी हुई किस्मों/कोटेशनों के सापेक्ष मूल्य की सामान्य गणितीय औसत के आधार पर वस्तु सूचकांक आसानी से तैयार किया जा सकता हैं। वस्तुओं के उप समूहों/समूहों/प्रमुख समूहों के लिए संकेतक उनसे संबद्ध शीर्षों के अंतर्गत आने वाली वस्तुओं/उप समूहों/समूहों के संकेतकों की भारित गणितीय औसत के आधार पर तय किए जाते हैं। थोक व्यापार और लेनदेन का प्रतिनिधि होने और साप्ताहिक आधार पर उपलब्ध होने के कारण

थोक मूल्य सूचकांक का इस्तेमाल परंपरागत दृष्टि से अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति के आकलन के लिए किया जाता है।

2.3 पिछले 07 वर्षों में मंहगाई की दर संबंधी जानकारी चार्ट 6.1 में दी गयी है।

चार्ट 6.1

भारत में मंहगाई की दर (थोक मूल्य सूचकांक) 2016–17 से 2022–2023

(प्रतिशत)

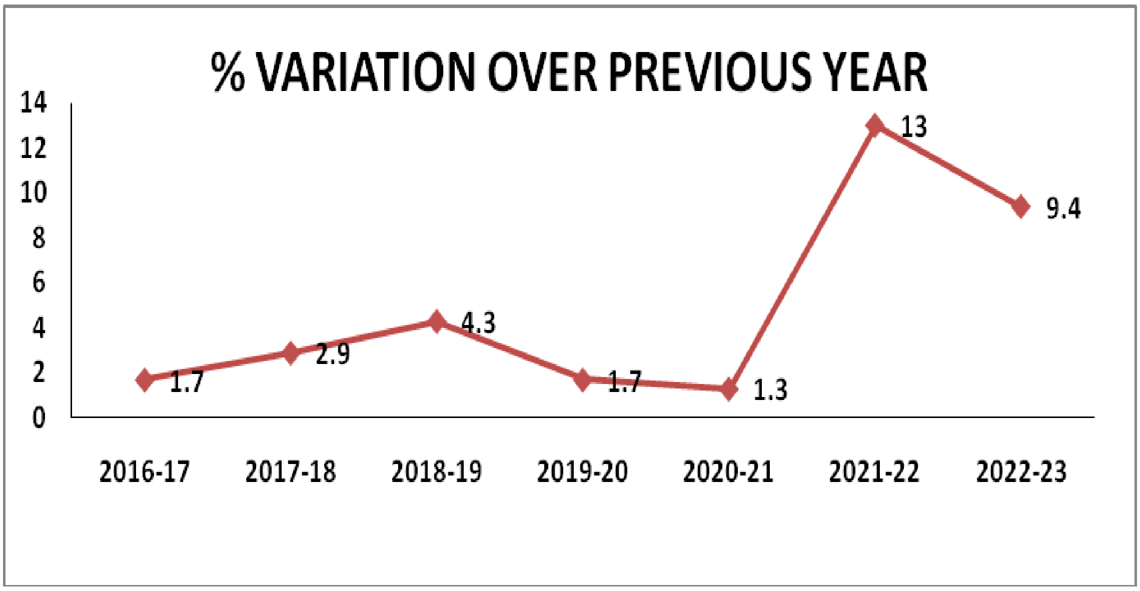

2.4 बृहत् आर्थिक एकीकरण की वजह से अंतर्राष्ट्रीय बाजारों की गतिविधियों का प्रभाव विश्व के सभी भागों में पहुंचने लगा है। इसके साथ ही इस एकीकरण की बदौलत वैश्विक बाजारों में विकासशील देशों को अधिक महत्वपूर्ण भूमिकाएं अदा करने के अवसर मिलने लगे हैं। इस संदर्भ में मौजूदा दशक में विकासशील देशों का महत्व बढ़ गया है क्योंकि भोजन, ऊर्जा और सामग्री की उनकी बढ़ती मांग के कारण लगता है कि मौजूदा वस्तु बाजार में मूल्य बढ़ रहे हैं।

2.5. खाद्य वस्तुओं के मूल्यों में बढ़ोत्तरी आज देश के समक्ष सर्वाधिक ज्वलंत मुद्दों में से एक है। मूल्य वृद्धि की कठिनाइयां समूचे भारत में और समाज के सभी वर्गों द्वारा महसूस की जा रही हैं। खाद्य वस्तुओं के मूल्यों में इस बढ़ोत्तरी का लाभ किसान या फसल उगाने वालों को नहीं पहुंच रहा है क्योंकि बाजार में भारी विसंगतियां हैं। मांग–आपूर्ति विसंगतियां और अक्षम आपूर्ति व्यवस्था की वजह से उत्पादक और अंतिम उपभोक्ता के बीच मूल्यों में व्यापक अंतराल पैदा हो रहा है।

2.6 इसके अतिरिक्त उत्पादन और उत्पादकता में कमी, बाजार में प्रचलित अक्षमताएं–सरकारी खरीद में समन्वित प्रयासों का अभाव, भंडारण सुविधाएं पर्याप्त न होने के कारण वस्तुओं की बर्बादी, आदि ऐसे मुद्दे हैं जिनसे खाद्य वस्तुओं के दाम तेजी से बढ़ रहे हैं। मौजूदा दौर में सरकारी गतिविधियों के अंतर्गत खाद्य उत्पादन और उत्पादकता में सुधार, कृषि क्षेत्र में निवेश बढ़ाने आदि उपायों पर बल दिए जाने की आश्यकता है। वर्ष 2015 से 2022 तक दिल्ली में कुछ आवश्यक वस्तुओं के औसत थोक मूल्यों संबंधी जानकारी विवरण 6.1 में दी गयी है।

विवरण 6.1

दिल्ली में चुनी हुई वस्तुओं के औसत थोक मूल्य –2015–22

क्र.स.	वस्तु	यूनिट	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1.	गेहू (308)	प्रति क्विंटल	1770	1800	1900	2100	2150	2100	2050	2240
2.	चना (ग्रारा)	प्रति क्विंटल	4200	4690	4500	4550	4300	4325	5600	5600
3.	चावल (बासमती)	प्रति क्विंटल	6300	6500	6800	7600	8150	7450	7650	7600
4.	दाल अरहर (धुली हुई)	प्रति क्विंटल	10200	11820	7000	7100	5450	8875	10200	9950
5.	दाल मूंग (छिलका)	प्रति क्विंटल	8425	9050	6800	6950	5700	8987	9900	9650
6.	दाल उड़द (छिलका)	प्रति क्विंटल	10200	11720	6900	6900	7800	9025	9800	9300
7.	सरसों का तेल (कच्ची घानी)	15 कि.ग्रा. टिन	1390	1490	1350	1400	1450	1790	2625	2500
8	घी (देसी) नम्बर 1	15 कि.ग्रा. टिन	5250	6800	10000	10500	16000	7500	7400	6500
9.	घी (वनस्पति)	15 कि.ग्रा. टिन	1000	1200	1250	1275	1265	1400	1770	2400
10.	केरोसिन ऑयल	प्रति लीटर	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
11.	हार्ड कोक	प्रति 40 कि.ग्रा.	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
12.	मांस	प्रति क्विंटल	22500	34500	28000	32000	40000	45000	49000	55000
13.	अंडे	प्रति 100 संख्या	400	540	400	425	450	500	500	450
14.	मिर्च (लाल)	प्रति क्विंटल	NA	9500	12000	12500	13500	17000	19000	21500
15.	हल्दी	प्रति क्विंटल	9500	9800	9000	9500	11000	10500	11000	11000
16.	चीनी	प्रति क्विंटल	3825	4150	3800	3500	3575	3580	3550	3600
17.	गुड़	प्रति क्विंटल	2900	4000	4200	4400	4200	4000	4250	5000
18.	आलू	प्रति क्विंटल	1675	1800	750	850	1500	2200	780	1300
19.	प्याज (खुश्क)	प्रति क्विंटल	1000	2375	1600	1200	950	2200	2185	1300

स्रोत : कृषि विपणन निदेशालय, राराक्षे दिल्ली सरकार

3. औद्योगिक श्रमिको के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई–आईडब्ल्यू)

3.1 उपभोक्ता मूल्य सूचकांक आमतौर पर रोजमर्रा उपभोग की जाने वाली नियत वस्तुओं के खुदरा मूल्यों की प्रवृत्तियों का मूल्यांकन करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। आर्थिक एवं सांख्यिकीय निदेशालय, रा.रा.क्षे दिल्ली सरकार, द्वारा चुने हुए बाजारों, जैसे तिलक नगर, सब्जी मंडी, शाहदरा, यमुना विहार/भजनपुरा, मंगोलपुरी, आजादपुर, बवाना, नजफगढ़, कोटला मुबारकपुर, गोविन्दपुरी/कालकाजी और समयपुर बादली से साप्ताहिक और मासिक आधार पर आवश्यक वस्तुओं के खुदरा मूल्य एकत्र किए जाते हैं। इन मूल्यों को श्रम ब्यूरो भेज दिया जाता है, ताकि औद्योगिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का संकलन किया जा सके। श्रम ब्यूरो, चंडीगढ़, दिल्ली सहित भारत में 88 चुने हुए केंद्रों के लिए मासिक आधार पर उपभोक्ता मूल्य सूचकांक संकलित एवं जारी करता है। औद्योगिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक की वर्तमान श्रृंखला का संकलन 2016=100 को आधार वर्ष मानकर किया जा रहा है। 2001=100 के आधार वाली पुरानी श्रृंखला के स्थान पर सितम्बर 2020 से 2016=100 के आधार वाली नई श्रृंखला अपना ली गयी है। 2016=100 के आधार वाली वर्तमान श्रृंखला में ऊपर वर्णित औद्योगिक श्रमिकों

के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आंकड़े संग्रह करने के लिए दिल्ली में चुने हुए 11 बाजारों को शामिल किया गया है।

3.2 श्रम ब्यूरो चंडीगढ़ ने अब 2001=100 आधार वर्ष की पुरानी शृंखला के स्थान पर नया आधार वर्ष प्रस्तावित किया गया है। 2016=100 आधार वर्ष वाली नई शृंखला के लिए, मूल्यों के संकलन की प्रक्रिया एक साथ शुरू कर दी गई है। नई शृंखलाओं के लिए पांच नए बाज़ार (बवाना, नजफगढ़, तिलक नगर, भजनपुरा/यमुनाविहार और कोटला मुबारकपुर) शामिल किए गए हैं और दो वर्तमान/पुराने बाजारों (रानीबाग और मोतीनगर) को निकाल दिया गया है।

3.3 इस संदर्भ में यह उल्लेख करना उचित है कि श्रम ब्यूरो चंडीगढ़, श्रम और रोजगार मंत्रालय, ने पत्र संख्या 114/1/2013–सीपीआई दिनांक 03 नवंबर, 2020, के तहत सीपीआई (आईडब्ल्यू) के लिए नए आधार वर्ष 2016=100 को मंजूरी प्रदान की और उसके परिणाम स्वरूप नई शृंखला 2016=100 की शुरुआत हुई और मौजूदा शृंखला (पुरानी श्रृंखला) आधार वर्ष 2001=100 को 03 नवंबर 2020 से बंद कर दिया गया।

विवरण 6.2
दिल्ली में औद्योगिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक

(आधार वर्ष 2016=100)

क्र.स.	समूह	वरीयता (प्रतिशत)	2022	2023	प्रतिशत परिवर्तन
1.	खाद्य एवं पेय पदार्थ	36.13	130.7	136.7	4.6
2.	पान, सुपारी, तंबाकू और मादक पदार्थ	0.84	138.7	143.9	3.7
3.	वस्त्र और फुटवियर	5.43	151.7	159.4	5.1
4.	आवास	24.29	120.4	123.0	2.2
5.	ईंधन और प्रकाश	7.05	117.1	121.4	3.7
6.	विविध	26.26	120.1	124.3	3.5
सामान्य सूचकांक		100.00	125.7	130.3	3.7

स्रोत : श्रम ब्यूरो, चंडीगढ़।

** डेटा जनवरी 2023 से नवंबर 2023 तक (11 महीने) की अवधि से संबंधित है।*

3.4 सूचकांक को छह समूहों के लिए अलग से तैयार किया गया है और फिर प्रत्येक समूह को वरीयता प्रदान करके संयुक्त किया गया है। उच्चतम वरीयता 36.13 प्रतिशत खाद्य एवं पेय पदार्थ समूह को दी गई है, इसके बाद विविध वस्तुओं को 26.26 प्रतिशत, आवास 24.29 प्रतिशत, ईंधन और प्रकाश 7.05 प्रतिशत, वस्त्र और फुटवियर 5.43 प्रतिशत, और पान, सुपारी, तंबाकू तथा नशीले पदार्थों को 0.84 प्रतिशत वरीयता दी गई। दिल्ली में 2021, 2022 और 2023* के दौरान औद्योगिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक की जानकारी विवरण 6.2 में प्रस्तुत की गई है।

3.5 विवरण 6.2 से पता चलता है कि वार्षिक औसत उपभोक्ता मूल्य सूचकांक 2022 में 125.7 पर था जो 2023 में बढ़कर 130.3 पर पहुंच गया, अर्थात् इसमें 4.6 अंकों की वृद्धि दर्ज हुई। दिल्ली में औद्योगिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में बढ़ोत्तरी 2022 की तुलना में 2023 के दौरान 3.7 प्रतिशत दर्ज हुई।

3.6 खाद्य एवं पेय पदार्थ समूह का सूचकांक 2022 में 130.7 से बढ़कर 2023 में 136.7 हो गया, जिसमें 4.6 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई। पान, सुपारी, तंबाकू और नशीले पदार्थों का सूचकांक 3.7 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज करते हुए 138.7 से बढ़कर 143.9 हो गया, वस्त्र और फुटवियर समूह का सूचकांक 5.1 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज करते हुए 151.7 से बढ़कर 159.4 हो गया। आवास सूचकांक भी 2.2 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज करते हुए 120.4 से बढ़कर 123.0 हो गया है। ईंधन और प्रकाश का सूचकांक 2022 में 3.7 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज करते हुए 117.1 से बढ़कर 121.4 हो गया। विविध समूह के अंतर्गत सूचकांक 3.5 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज करते हुए 120.1 से बढ़कर 124.3 अंक हो गया। इस प्रकार वर्ष 2023 में मुद्रास्फीति दर में सबसे अधिक वृद्धि वस्त्र और फुटवियर समूह में हुई है।

4. अन्य महानगरों में मूल्य स्थिति

4.1 देश में अधिकांश नागरिकों के लिए महंगाई एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। विकास का मतलब है हमारे बच्चों के लिए बेहतर जीवन। पिछले कुछ वर्षों में आवश्यक वस्तुओं के दाम बढ़े हैं। ''प्याज, आलू और गेहूं जैसी कुछ चीजों में मौसमी उतार–चढ़ाव, प्रमुख उत्पादन क्षेत्रों में खराब मौसम, परिवहन संबंधी अड़चनों, ढुलाई लागत में बढ़ोतरी और इन चीजों के भंडार में कमी की वजह से दामों में वृद्धि को छोड़कर, अधिकतर आवश्यक वस्तुओं के खुदरा दामों में भारत के सभी महानगरों में स्थिरता का रुझान देखा गया है। 2019 से 2023 के दौरान भारत के महानगरों में औद्योगिक मजदूरों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के बारे में जानकारी विवरण 6.3 में दी गयी है।

विवरण 6.3
भारत के महानगरों में 2019–2023 के दौरान औद्योगिक मजदूरों का उपभोक्ता मूल्य सूचकांक

(औसत वार्षिक सूचकांक)

क्र सं	वर्ष	अखिल भारत	प्रतिशत परिवर्तन	दिल्ली	प्रतिशत परिवर्तन	कोलकाता	प्रतिशत परिवर्तन	चेन्नई	प्रतिशत परिवर्तन	मुम्बई	प्रतिशत परिवर्तन
1.	2019	110.2	7.6	107.5	10.3	118.6	5.0	113.4	5.3	107.2	6.2
2.	2020	116.4	5.6	111.8	4.0	124.2	4.7	118.2	4.2	112.3	4.8
3.	2021	122.0	4.8	116.4	4.1	126.0	1.4	122.5	3.6	116.6	3.8
4.	2022	129.2	5.9	125.7	8.0	137.4	9.0	127.3	3.9	122.7	5.2
5.	2023	136.4	5.6	130.3	3.7	139.6	1.6	135.1	6.1	127.7	4.1

स्रोत : लेबर ब्यूरो चंडीगढ़

4.2 विवरण 6.3 में यह बात ध्यान देने की है कि वर्ष 2022 में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सामान्य) अखिल भारतीय स्तर पर 129.2 के स्तर पर रहा। सबसे उच्च सूचकांक कोलकाता के लिए 137.4 था जबकि उसके बाद क्रमशः चेन्नई के लिए 127.3, दिल्ली के लिए 125.7 और मुंबई के लिए 122.7 रहा। पूरे भारत में वर्ष 2023 के लिए औसत उपभोक्ता मूल्य सूचकांक संख्या (सामान्य) 136.4 दर्ज की गई। कोलकाता के लिए, यह क्रमशः 139.6, उसके बाद चेन्नई 135.1, दिल्ली 130.3 और मुंबई 127.7 रहा। 2022 और 2023 के दौरान भारत में मेट्रो शहरों के औद्योगिक श्रमिकों के लिए समूह–वार मूल्य सूचकांक संबंधी जानकारी तालिका 6.2 में प्रस्तुत की गई है।

4.3 2019 से 2023 के दौरान दिल्ली और चुने हुए महानगरों में औद्योगिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक चार्ट 6.2 में प्रदर्शित किया गया है।

चार्ट 6.2

2019–23 में दिल्ली और अन्य महानगरो में औद्योगिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक

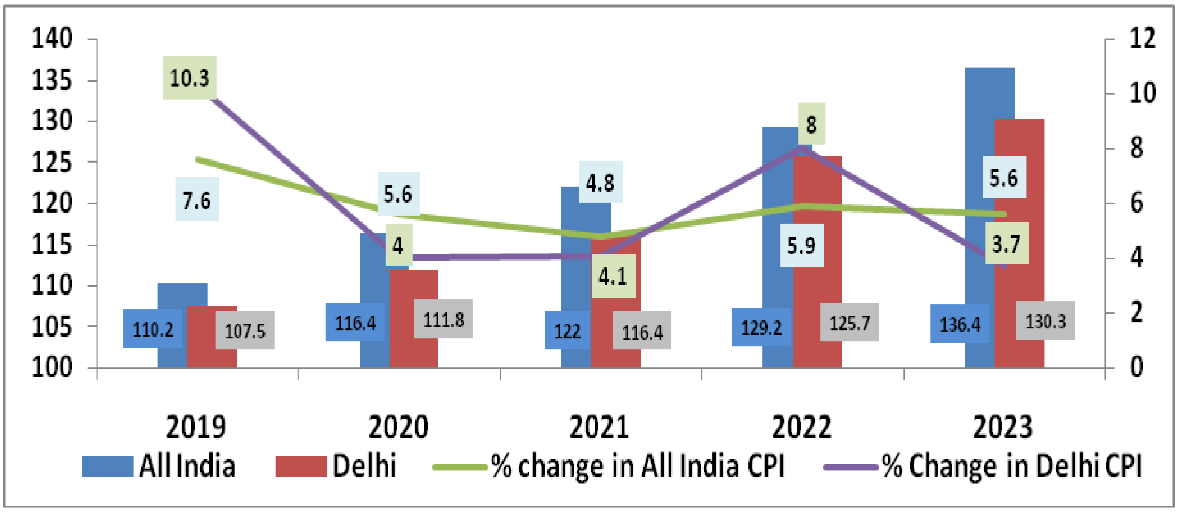

5. आधार वर्ष 2016 = 100 के साथ सीपीआई (आईडब्ल्यू) की नई श्रृंखला

5.1 विवरण 6.4 से देखा जा सकता है कि नए आधार वर्ष (2016=100) के अनुसार, वर्ष 2022–2023 के दौरान महानगरों में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सामान्य), सबसे कम मुद्रास्फीति की दर चेन्नई में (4.5 प्रतिशत) रही, जबकि सबसे अधिक कोलकाता में (8.2 प्रतिशत) दर्ज हुई। इसके बाद अन्य मेट्रो शहरों में दिल्ली (7.9 प्रतिशत) और मुबंई (5.2 प्रतिशत) का स्थान है। वर्ष 2022–2023 के दौरान अखिल भारतीय स्तर पर मुद्रास्फीति की दर 6.1 प्रतिशत रही।

विवरण 6.4

अखिल भारतीय स्तर पर महानगरों में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (वित्तीय वर्ष–वार)

(नया आधार वर्ष 2016 =100)

	2021-22	2022-23	प्रतिशत में
अखिल भारतीय	123.6	131.1	6.1
दिल्ली	118.3	127.6	7.9
मुम्बई	118.0	124.1	5.2
चेन्नई	123.5	129.0	4.5
कोलकाता	128.2	138.7	8.2

राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा 2012=100 आधार पर जारी उपभोक्ता मूल्य सूचकांक संबंधी आंकड़े।

5.2 राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (एनएसओ), सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय हर महीने 2012=100 के आधार पर सीपीआई (ग्रामीण, शहरी, संयुक्त) जारी कर रहा है। दिल्ली और अखिल भारत में सीपीआई (संयुक्त) पर आधारित मुद्रास्फीति दरों की महीनेवार तुलनात्मक स्थिति विवरण 6.5 (जनवरी 2020 से दिसंबर 2020 के महीनों के लिए), विवरण 6.6 (जनवरी 2021 से दिसंबर 2021 के महीनों के लिए), विवरण 6.7 (जनवरी 2022 से दिसंबर 2022 के महीनों के लिए) और विवरण 6.8 (जनवरी 2023 से दिसंबर 2023 के महीनों के लिए) में दर्शायी गयी है।

विवरण 6.5

दिल्ली और अखिल भारत में सीपीआई (संयुक्त) पर आधारित महंगाई दर जनवरी 2020 से दिसंबर 2020 तक (नए आधार वर्ष 2012 के साथ)

वर्ष	महीना	दिल्ली (प्रतिशत)	अखिल भारत (प्रतिशत)
2020	जनवरी	4.69	7.59
2020	फरवरी	3.46	6.58
2020	मार्च	2.88	5.84
2020	अप्रैल	*	7.22
2020	मई	*	6.27
2020	जून	1.69	6.23
2020	जुलाई	3.6	6.73
2020	अगस्त	3.58	6.69
2020	सितंबर	4.78	7.27
2020	अक्टूबर	3.85	7.61
2020	नवंबर	3.36	6.93
2020	दिसंबर	1.23	4.59
वार्षिक मुद्रास्फीति दर		3.31	6.63

* *मुद्रास्फीति की दर की गणना नहीं की जा सकती क्योंकि वर्ष 2020 के लिए कोविड महामारी के कारण एनएसओ द्वारा डेटा प्रदान नहीं किया गया है।*

विवरण 6.6

दिल्ली और अखिल भारत में सीपीआई (संयुक्त) पर आधारित महंगाई दर जनवरी 2021 से दिसंबर 2021 तक (नए आधार वर्ष 2012 के साथ)

वर्ष	महीना	दिल्ली (प्रतिशत)	अखिल भारत (प्रतिशत)
2021	जनवरी	1.83	4.06
2021	फरवरी	2.94	5.03
2021	मार्च	3.49	5.52
2021	अप्रैल	*	4.23
2021	मई	*	6.30
2021	जून	6.86	6.26
2021	जुलाई	5.28	5.59
2021	अगस्त	5.31	5.30
2021	सितंबर	4.89	4.35
2021	अक्टूबर	6.15	4.48
2021	नवंबर	7.04	4.91
2021	दिसंबर	6.55	5.66
वार्षिक मुद्रास्फीति दर		5.03	5.14

* *मुद्रास्फीति की दर की गणना नहीं की जा सकती क्योंकि वर्ष 2021 के लिए कोविड महामारी के कारण एनएसओ द्वारा डेटा प्रदान नहीं किया गया है।*

विवरण 6.7

दिल्ली और अखिल भारत में सीपीआई (संयुक्त) पर आधारित महंगाई दर जनवरी 2022 से दिसंबर 2022 तक (नए आधार वर्ष 2012 के साथ)

वर्ष	महीना	दिल्ली (प्रतिशत)	अखिल भारत (प्रतिशत)
2022	जनवरी	6.14	6.01
2022	फरवरी	5.70	6.07
2022	मार्च	5.75	6.95
2022	अप्रैल	6.58	7.79
2022	मई	5.57	7.04
2022	जून	5.06	7.01
2022	जुलाई	4.13	6.71
2022	अगस्त	4.16	7.00
2022	सितंबर	4.03	7.41
2022	अक्टूबर	2.99	6.77
2022	नवंबर	2.17	5.88
2022	दिसंबर	2.98	5.72
वार्षिक मुद्रास्फीति दर		4.61	6.70

विवरण 6.8

दिल्ली और अखिल भारत में सीपीआई (संयुक्त) पर आधारित महंगाई दर जनवरी 2023 से दिसंबर 2023 तक (नए आधार वर्ष 2012 के साथ)

वर्ष	महीना	दिल्ली (प्रतिशत)	अखिल भारत (प्रतिशत)
2023	जनवरी	3.27	6.52
2023	फरवरी	3.64	6.44
2023	मार्च	3.44	5.66
2023	अप्रैल	2.22	4.70
2023	मई	1.53	4.31
2023	जून	1.98	4.87
2023	जुलाई	3.78	7.44
2023	अगस्त	3.09	6.83
2023	सितंबर	2.24	5.02
2023	अक्टूबर	2.48	4.87
2023	नवंबर	3.10	5.55
2023	दिसंबर*	2.95	5.69
वार्षिक मुद्रास्फीति दर		2.81	5.65

* *अस्थायी*

अध्याय एक नजर में

➢	औद्योगिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई–आईडब्ल्यू) प्रमुख आर्थिक संकेतकों में से एक है, जो आधार वर्ष के संदर्भ में श्रमिक वर्ग के औसत परिवार द्वारा उपभोग की जाने वाली वस्तुओं और सेवाओं के निश्चित समूह के संबंध में निर्दिष्ट क्षेत्र एवं समयावधि में खुदरा कीमतों में सापेक्ष परिवर्तन को मापता है।
➢	सीपीआई के संकलन के लिए अपनाई गई मूल्य की परिभाषा वह मूल्य है जो एक उपभोक्ता/औद्योगिक कार्यकर्ता को निर्दिष्ट इकाई के लिए निर्दिष्ट वस्तु/किस्म के लिए चयनित बाजार की चयनित दुकान में भुगतान करना पड़ता है। इसमें बिक्री कर आदि जैसे सभी कर शामिल हैं, और छूट और रियायतें शामिल नहीं हैं, जो सभी ग्राहकों के लिए सार्वभौमिक रूप से लागू हैं।
➢	थोक मूल्य सूचकांक (डब्ल्यूपीआई) एकमात्र सामान्य सूचकांक है जो व्यापक रूप से कीमतों में उतार–चढ़ाव को पकड़ता है और सभी व्यापार और लेनदेन में वस्तुओं की कीमतों में उतार–चढ़ाव का संकेतक है। इसे आम तौर पर अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति की दर के संकेतक के रूप में समझा जाता है।
➢	सितंबर, 2020 के महीने से श्रम ब्यूरो ने सीपीआई–आईडब्ल्यू (2001=100) की पुरानी श्रृंखला के आधार को नए आधार वर्ष 2016=100 में अपडेट किया है।
➢	उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई) किसी समयावधि में निर्दिष्ट वस्तुओं और सेवाओं की खुदरा कीमतों में परिवर्तन का प्रतिबिंब है, जबकि थोक मूल्य सूचकांक (डब्ल्यूपीआई) थोक स्तर पर वस्तुओं के सामान्य मूल्य स्तर में परिवर्तन को दर्शाता है।